भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2004

जिसका उत्तर 09.12.2021 को दिया जाना है

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क

2004. श्रीमती कविता मलोथू:

डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:

डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:

श्री दयाकर पसुनूरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैदराबाद में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत के लॉजिस्टिक लागत की तुलना अन्य विकसित देशों से की जा सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त लागत को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) लॉजिस्टिक पार्कों की स्थापना के बाद लॉजिस्टिक लागत जो वर्तमान मं 13 से 15 प्रतिशत है, में कितनी कमी होने का अनुमान है;

(घ) हैदराबाद में लॉजिस्टिक पार्क को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ड.) क्या उक्त लॉजिस्टिक पार्क पर कोविड महामारी के कारण कोई प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने अक्टूबर 2017 में 5.35 लाख करोड़ रूपये के निवेश के साथ भारतमाला परियोजना को मंजूरी दी थी जिसमें पूरे देश में 34,800 किलोमीटर के राजमार्ग शामिल हैं।

भारतमाला परियोजना में पूरे देश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) का विकास भी शामिल है और 35 एमएमएलपी की सूची में एमएमएलपी हैदराबाद शामिल है।

(ख) अमेरिका जैसे विकसित देशों में 8-9% की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का 13-14% है। भारत सरकार द्वारा देश में लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने के लिए कई पहल की गई हैं। जैसे:-

(i) लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने के लिए 35 रणनीतिक स्थानों पर एमएमएलपी का विकास करना। इन 35 एमएमएलपी से लगभग 50% सड़क माल ढुलाई पूरा होने की उम्मीद है। इन एमएमएलपी से निर्बाध इंटरमॉडल फ्रेट ट्रांसफर को सक्षम करने और प्रमुख कार्गो समेकन और वितरण केंद्र के रूप में काम करने की उम्मीद की

जाती है। यह देश में और अधिक कुशल माल ढुलाई की आवाजाही को सक्षम बनाएगा, जिससे लॉजिस्टिक लागत और समय में कमी आएगी। 35 एमएमएलपी की सूची अनुबंध-1 में दी गई है।

(ii) भारतमाला परियोजना के तहत, 34,800 किलोमीटर राजमार्ग / एक्सप्रेसवे शामिल हैं, जिनसे देश में 70-80% माल ढुलाई की उम्मीद की जाती है।

(iii) पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर योजना को हाल ही में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समग्र निगरानी और समीक्षा के लिए शुरू किया गया है, जिनसे लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ावा देने की उम्मीद है। इसमें समन्वित कार्यक्रम समीक्षा के लिए भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइनफॉरमैटिक्स (बीआईएसएजी-एन) के सहयोग से योजनाबद्ध गतिशील भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित ईआरपी प्लेटफॉर्म भी शामिल है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण आर्थिक विकास को सक्षम बनाएगा और वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करेगा।

(ग) मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों से परिवहन के विभिन्न तरीकों में माल के निर्बाध अंतरण को सक्षम बनाने की आशा की जाती है, जिससे रेल/महासागर/अंतर्देशीय जलमार्ग या बड़े आकार के ट्रक और ट्रकों पर फर्स्ट माइल/लास्ट माइल मूवमेंट जैसे अधिक कुशल मोड पर हब-टू-हब लाइन के साथ माल ढुलाई के हब और स्पोक मॉडल को सक्षम बनाया जा सके। मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) से भी प्रमुख सेवाएं जैसे कि उन्नत भंडारण अवसंरचना, फ्रेट नेटवर्क में प्रमुख नोड्स के लिए पहली और अंतिम मील कनेक्टिविटी, और मूल्य वर्धित सेवाएं जैसे कि कस्टम क्लेरेंस और लेट स्टेज प्रसंस्करण गतिविधियों के प्रावधान प्रदान करने की उम्मीद है। इन एमएमएलपी का उद्देश्य लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना है। हालांकि, लॉजिस्टिक लागत में प्रत्याशित कमी कई कारकों पर निर्भर है जैसे वाहन बेड़े मिश्रण और दक्षता, बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी की ताकत (सड़क / रेल / शिपिंग / वायु), कई प्लेयर्स द्वारा लाई गई आपूर्ति श्रृंखला दक्षता, आदि और इसलिए इस स्तर पर मूल्यांकन किया जा सकता है।

(घ) एमएमएलपी को राज्य सरकार के सहयोग से विकसित किया जाना है। एमएमएलपी हैदराबाद के लिए, 09 अगस्त, 2021 को राज्य सरकार (टीएसआईआईसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमएमएलपी हैदराबाद के लिए डीपीआर तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है और राज्य सरकार के पास जमीन की उपलब्धता के आधार पर डीपीआर की प्रक्रिय पूरा होने को है। इन एमएमएलपी को पीपीपी मोड पर विकसित किया जाना है और चरण -1 के निर्माण शुरू होने से 2 साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

(ङ) जी, नहीं।

अनुबंध-1

'मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के संबंध में' श्रीमती कविता मलोथू, डॉ. जी. रणजीत रेड्डी, डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता, श्री दयाकर पसुनूरी द्वारा पूछे गये दिनांक 09.12.2021 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं.2004 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क के प्रस्तावित स्थानों की सूची

क्र. सं.	स्थान
1	असम
2	नागपुर
3	चेन्नई
4	बैंगलोर
5	हैदराबाद
6	इंदौर
7	मुंबई
8	कोयंबटूर
9	पुणे
10	सूरत
11	संगरूर
12	दिल्ली एनसीआर
13	उत्तर गुजरात
14	उत्तरी पंजाब
15	जयपुर
16	कोलकाता
17	अंबाला
18	जगतसिंहपुर
19	नासिक

20	कोटा
21	पणजी
22	हिसार
23	विशाखापत्तनम
24	भोपाल
25	सुंदरगढ़
26	भटिंडा
27	एक प्रकार का हंस
28	राजकोट
29	रायपुर
30	जम्मू
31	कांडला
32	कोचीन
33	सिंगरौली
34	अनंतपुर
35	साहिबगंज

****